RNI. No. MAHHIN-2014/55445 Postal Reg.No. NPCity/437/2023-2025 www.kendriyamanavadhikar.com

केन्द्रीय सम्माननीय जीवन समान अधिकार दैनिक

मानवाधिकार

| नागपुर. सोमवार, 4 अगस्त 2025 | वर्ष - 13 | अंक - 159 | पृष्ठ - 4 | मुल्य - 2 रु. संपादक : मिलिंद दहिवले

दैनिक केन्द्रीय मानवाधिकार
हिन्दी समाचारपत्र के लिए चाहिए
पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर, फोटोग्राफर, काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट, मार्केटिंग विभाग इंचार्ज, न्यूज़ एंकर, वीडियो एडिटर, टेलीकॉलर, इवेन्ट मैनेजर
M/F उमेदवार शीघ्र संपर्क करे
- मुख्य कार्यालय -
प्लॉट नं. 386, चंदन नगर, नागपुर-440 024
संपर्क - 9552011005

मुख्यमंत्री ने मोर्शी में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला रखी, कृषि का दर्जा मिलेगा

अमरावती - राज्य सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया है। इस दर्जा मिलने से मत्स्य पालकों को ऋण, किसान क्रेडिट और संबंधित मामलों में प्राथमिकता मिलने में मदद मिली है। इसके कारण, मत्स्य पालन आज एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा।

महाराष्ट्र के चौथे और पश्चिमी विदर्भ के पहले मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का शिलान्यास मोर्शी में हुआ। इस अवसर पर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, मत्स्यपालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे, सांसद अनिल बोंडे, विधायक प्रताप अडसड, केवलराम काले, उमेश यावलकर, राजेश वानखेड़े, प्रवीण तायड़े, चैनसुख संचेती, रामदास तड़स, नवनीत राणा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विकास विभाग के सचिव डॉ. रामास्वामी एन., महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के कुलपति डॉ. नितिन पाटिल, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिला कलेक्टर आशीष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा, कार्यकारी सदस्य अनुराधा चव्हाण और अन्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। हालाँकि समुद्री मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, लेकिन आज 40 प्रतिशत मत्स्य पालन मीठे पानी में किया जाता है। इसे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। सरकार की मदद से, किसानों ने कृषि के लिए सिंचाई के साथ-साथ खेत के तालाबों में मत्स्य पालन शुरू किया है, जिससे उन्हें कठिन समय में मदद मिली है। रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आपदाग्रस्त स्थितियों में मदद करने के लिए एक नीति तय की गई है। मुख्य रूप से कृषि के लिए सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। विदर्भ की भाग्य रेखा कही जाने वाली वैनगंगा-नलगंगा की साढ़े पाँच किलोमीटर की परियोजना, गोसेखुर्द के पानी को बुलढाणा तक लाएगी। इसमें 31 बांध भरे जाएंगे और इस परियोजना पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। किसानों की मदद के साथ-साथ कृषि में निवेश करना आवश्यक है। इसके लिए पाँच वर्षों में 25 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, यानी हर साल 5 हज़ार करोड़ रुपये।

.....आखरी पेज पर

न्यूज गैलरी

लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे के वंचितों के विकास के मार्ग पर चलेगी सरकार – मुख्यमंत्री

नागपुर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार वंचितों के विकास के मार्ग पर चलेगी, जैसा कि साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे ने अपने कार्यों के माध्यम से दिखाया है। साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे चौक स्थित अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे के गीतों ने संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन को जीवित रखा और समाज के वंचितों की आवाज को जन-जन तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से यह प्रस्तुत किया कि धरती शेषनाग के सिर पर नहीं, बल्कि कार्यकर्ता की हथेली पर टिकी है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार उनके दिखाए वंचितों के विकास के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगी। इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, विधायक अभिजीत वंजारी और संदीप जोशी, नगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी और अन्य उपस्थित थे जिन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की।

स्व-निहित श्रेणी में विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा बोर्डों से विभिन्न रियायतें

मुंबई - 16 अक्टूबर 2018 के सरकारी निर्णय के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र और उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षाओं में शामिल होने वाले विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उनकी सीखने की शैली के आधार पर बोर्ड द्वारा विभिन्न रियायतें दी जाती हैं। ऑटिज़्म से पीड़ित विद्यार्थियों को दी जाने वाली रियायतों के संबंध में विभिन्न मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, बोर्ड द्वारा यह स्पष्ट किया गया है। केंद्र सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र निर्धारित किया है और यदि किसी छात्र के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र के स्थान पर ऐसा विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र है और उसने दिव्यांगता प्रस्ताव के साथ उक्त प्रमाण पत्र संभागीय बोर्ड कार्यालय में जमा कर दिया है, तो ऐसे छात्रों से विभिन्न रियायतों के लिए जिला शल्य चिकित्सक के प्रतिहस्ताक्षर सहित निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जानी चाहिए। सभी संभागीय बोर्डों को दिनांक 23 नवंबर 2023 के पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है। तदनुसार, बोर्ड द्वारा दिव्यांग छात्रों को नियमानुसार विभिन्न रियायतें दी जाती हैं। उपरोक्त के अनुसार, वर्ष 2023-24 से कार्रवाई की जा रही है और मंडल ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी दिव्यांग छात्र निर्धारित सुविधाओं से वंचित न रहे। यदि किसी छात्र के पास आत्मनिर्भरता प्रमाण पत्र (विशिष्ट विकलांगता एचडी कार्ड) नहीं भी है, तो भी यदि उसके पास निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र है, तो मंडल ऐसे दिव्यांग छात्रों को नियमानुसार विभिन्न रियायतें प्रदान करने के लिए कार्रवाई करता है। इसलिए, संबंधित प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, अभिभावकों और छात्रों को इस संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव देवीदास कुलाल ने कहा।

गोंडा के दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये

नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई एक दुर्घटना में जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। पीएमओ इंडिया के हैंडल से एक्स पर पोस्ट में कहा: ''उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई एक दुर्घटना में जान-माल की हानि से अत्यंत दुःखी हूं। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। ईश्वर करे कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: प्रधानमंत्री @ narendramodi''

बेंगलुरु में आईओटी और एआई के लिए के-टेक एमईआईटीवाई नैसकॉम केंद्र

नई दिल्ली - उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एनआईसीडीसी के सीईओ एवं एमडी, डीपीआईआईटी के निदेशक और स्टार्टअप इंडिया के प्रमुख श्री रजत कुमार सैनी के साथ बेंगलुरु स्थित के-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नैसकॉम उत्कृष्टता केंद्र (आईओटी एवं एआई) का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य स्टार्टअप्स और इनक्यूबेशन क्षेत्र के अग्रणी लोगों से जुड़ना, स्थानीय नवाचार इको-सिस्टम की जानकारी प्राप्त करना और विकास को गति देने के लिए नीतिगत समर्थन के अवसरों की पहचान करना था।

भारत का सबसे बड़ा डीप टेक इनोवेशन सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, उद्यमों, शिक्षाविदों और सरकार को जोड़ता है ताकि आईओटी, एआई, डेटा साइंस, बिग डेटा, एआर/वीआर, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान किया जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने स्टार्टअप संस्थापकों और इनक्यूबेशन प्रबंधकों के साथ बातचीत की ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये तकनीकें विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और शहरी समाधानों के भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकती हैं। बेंगलुरु में निवेशक गोलमेज सम्मेलन के बाद, डीपीआईआईटी के सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख परियोजना, तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र की विस्तृत समीक्षा की। डीपीआईआईटी सचिव ने 1,736 एकड़ क्षेत्र में फैले चरण-ए के विकास, आंतरिक सड़कों, जल निकासी और उपयोगिता गलियारों की प्रगति और निवेशकों को समर्थन देने की पहलों सहित प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की।

ईपीसी कांट्रेक्टर लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और परियोजना के लिए पीएमसी कांट्रेक्टर हास्कोनिंगडीएचवी के साथ बैठक के दौरान, निर्माण प्रगति और प्रमुख उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी दी गई। एलएंडटी ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि वे काम में तीव्रता लाकर प्रमुख कार्यों को समय पर पूरा करेंगे ताकि वर्ष के अंत तक उद्योगों को भूमि आवंटन शुरू हो सके। भाटिया ने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए निर्धारित समय पर नियोजित लक्ष्यों को पूरा करें, ताकि तुमकुरु औद्योगिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित कर सके। प्रतिनिधिमंडल ने फॉक्सकॉन होन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और देवनहल्ली एयरोस्पेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन (#एसईजेड) का भी दौरा किया।

कोल्हापुरी चप्पल जीआई टैग का आधिकारिक स्वामित्व लिडकॉम और लिडकर कॉर्पोरेशन को

मुंबई - महाराष्ट्र और कर्नाटक के पारंपरिक और ऐतिहासिक जूते, कोल्हापुरी चप्पल को भौगोलिक संकेत चिह्न (#GITag) प्राप्त हुआ है। इस GI टैग का आधिकारिक पंजीकृत स्वामित्व दो निगमों, संत रोहिदास चमड़ा उद्योग एवं चर्मकार विकास निगम लिमिटेड (#LIDCOM) और डॉ. बाबू जगजीवनराम चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड (#LIDKAR) के पास है, दोनों निगमों के प्रबंध निदेशकों ने स्पष्ट किया है। जून 2025 में, प्रसिद्ध इतालवी ब्रांड 'प्रादा' ने पुरुषों के लिए अपना 'स्प्रिंग/समर' कलेक्शन पेश किया। इस फैशन शो में मॉडल द्वारा पहने गए चमड़े के सैंडल का डिज़ाइन महाराष्ट्र के पारंपरिक और जीआई पंजीकृत कोल्हापुरी चप्पलों से काफी मिलता-जुलता पाया गया। इस घटना के बाद, सोशल मीडिया और पारंपरिक कारीगर समूहों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसके बाद, वकीलों के एक समूह ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (#PIL) दायर की, जिसमें प्रादा को भौगोलिक संकेत (GI टैग) द्वारा संरक्षित कोल्हापुरी चप्पलों के समान डिज़ाइन का उपयोग करके कानून का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी गई। 16 जुलाई, 2025 को, पीठ ने इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि कोल्हापुरी चप्पलों के भौगोलिक संकेत (GI) चिह्न के पंजीकृत धारक, अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक चमड़ा उद्योग विकास निगम, ही ऐसे मामलों में वास्तविक शेयरधारक हैं, और इसलिए, उन्हें ऐसी दीवानी कार्रवाई दायर करने का कानूनी अधिकार है। इस संदर्भ में कोल्हापुरी ग्लोबल जीआई टैग के आधिकारिक पंजीकृत मालिक लिडकॉम और लिडकर कॉर्पोरेशन ने संयुक्त रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को किसी भी तरह से 'प्रादा' या इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संवाद, चर्चा या प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। कोल्हापुरी जूतों का इतिहास 12वीं सदी की संत परंपरा से लेकर 20वीं सदी में राजर्षि शाहू महाराज की प्रगतिशील नीतियों तक जुड़ा हुआ है। लिडकॉम और लिडकर का संयुक्त उद्देश्य न केवल भौगोलिक संकेत की रक्षा करना है।

मंगलागिरी में 272 किमी की राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी

नई दिल्ली - केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5,233 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ 272 किलोमीटर की 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री श्री किंजरापु राम मोहन नायडू, श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। नितिन गडकरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, इन परियोजनाओं को दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने, परिवहन लागत को कम करने, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी को मजबूत करने और तिरुपति, नेल्लोर और रायचोटी जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है - जिससे आंध्र प्रदेश भारत की विकास गाथा में सबसे आगे होगा।'' गडकरी ने भारत की लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय गिरावट पर भी प्रकाश डाला। बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण लॉजिस्टिक्स लागत 16 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गई है और दिसंबर 2025 तक इसके 9 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। इस कमी से निर्यात दोगुना होने और रोजगार में वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि एनएचएआई के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 120 प्रतिशत हो गई है, जो कि वर्ष 2014 में 4,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2025 में 8,700 किलोमीटर हो गई। यह विकास सरकार के बुनियादी ढांचे पर आधारित आर्थिक विकास के प्रभावशाली ध्यान केन्द्रित करने को रेखांकित करता है। एनएच-71 के मदनपल्ले से पिलेरू तक के खंड को 1,994 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 56 किलोमीटर लंबे आधुनिक 4-लेन कॉरिडोर में बदल दिया गया है। इस महत्वपूर्ण उन्नयन में 9 फ्लाईओवर, एक रेल ओवरब्रिज, 19 प्रमुख पुल, 5 वाहन अंडरपास और 10 स्थानीय अंडरपास शामिल हैं। इसी प्रकार, एनएच-340सी के कुरनूल से मंडलेम खंड को 31 किलोमीटर लंबे पक्के शोल्डर के साथ 4-लेन सड़क में अपग्रेड किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की महाराष्ट्र सहित बहु-लेन परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली - भारतीय रेल नेटवर्क का भी 574 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर लगभग 11,169 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की चार परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी। इन परियोजनाओं की लागत 11,169 करोड़ रुपये होगी। चार परियोजनाओं में इटारसी-नागपुर चौथी लेन, छत्रपति संभाजीनगर-परभणी दोहरीकरण, अलुआबारी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लेन, डांगोआपोसी-जारोली तीसरी और चौथी लेन शामिल हैं।

बढ़ी हुई ट्रैक क्षमता से इन मार्गों पर यातायात की गति में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे भारतीय रेलवे के संचालन की दक्षता और सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार होगा। इन मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्तावों के क्रियान्वयन से न केवल रेलवे के संचालन में सुधार होगा, बल्कि यातायात में देरी की संख्या में भी कमी आएगी। ये सभी परियोजनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत न्यू इंडिया के विजन के अनुरूप हैं। इन परियोजनाओं से संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा और वहाँ रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अवसर बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी।

इन परियोजनाओं को एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने पर ज़ोर देते हुए डिज़ाइन किया गया है। तदनुसार, ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर आधारित होंगी। ये परियोजनाएँ यात्री परिवहन सहित वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। ये चार परियोजनाएँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करेंगी। इससे भारतीय रेल नेटवर्क का लगभग 574 किलोमीटर विस्तार होगा। ये प्रस्तावित बहु-मार्गीय परियोजनाएँ लगभग 43.60 लाख की आबादी वाले लगभग 2,309 गाँवों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

जिन मार्गों पर ये परियोजनाएँ क्रियान्वित की जानी हैं, वे कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी थोक वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से इन मार्गों के क्षमता विस्तार से प्रति वर्ष 95.91 मिलियन टन की अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता सृजित होगी। परिवहन का एक पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल साधन होने के नाते, रेलवे जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने और रसद लागत में बचत करने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही, यह तेल आयात की आवश्यकता को भी कम करेगा और कार्बन उत्सर्जन को 20 करोड़ पेड़ लगाने के लाभों के बराबर कम करेगा।

संपादक की कलम से

रिक्त पदों की भर्ती कब

मिलिंद दहिवले
संपादक

केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40,35,203 थी। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में पद और आवश्यकता के आधार पर रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियों और की गई नियुक्तियों का विवरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा, व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में स्वीकृत पदों और पदस्थ व्यक्तियों से संबंधित समेकित आंकड़ों वाली वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। सरकार ने सभी मंत्रालयों/ विभागों को सीधी भर्ती के माध्यम से रिक्त/ अपूर्ण पदों को भरने के लिए समय पर और अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों को सीधी भर्ती के पदों के संबंध में अपनी रिक्तियों की स्थिति की सूचना संबंधित भर्ती एजेंसियों को देने के लिए अग्रिम कार्रवाई करनी होगी।

स्व.भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर.....

नागपुर – समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण नितिन जी के कार्यों का केंद्र रहा है। वे हाशिए पर पड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके विशेष कार्य हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर इसी कड़ी में शामिल हैं।" उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ा कदम है।

एक ओर जहाँ चिकित्सा क्षेत्र में उन्नत तकनीक का उपयोग बढ़ा है, वहीं सेवाओं की लागत भी अधिक है। ऐसे में, यदि एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें भारतीय निर्मित होंगी, तो सेवाओं की लागत भी कम होगी। साथ ही, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भविष्य में अस्पतालों की संख्या बढ़ानी होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करते समय सेवा और सहानुभूति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगले चार वर्षों में महाराष्ट्र में देश की सबसे अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली बनाई जाएगी और सिकलसेल, थैलेसीमिया और एनीमिया के उपचार के लिए एक नई योजना तैयार की जाएगी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम व्यक्ति, वंचितों की सेवा करने, उनके जीवन को सहने योग्य बनाने के लिए अंत्योदय का विचार दिया। मैं उस मार्ग पर निरंतर काम कर रहा हूं। राजनीति का सही अर्थ राष्ट्रसेवा, समाजसेवा और सेवा है। इसलिए, मैं इस बारे में सोचता रहता हूं कि मैं अपने काम के माध्यम से गरीबों के जीवन को कैसे बदल सकता हूं। उसी प्रेरणा से, कई लोगों के सहयोग से, स्वर्गीय भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संतोष व्यक्त किया कि वह उस माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में सक्षम थे जिसने उन्हें जन्म दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह केंद्र व्यवसाय का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। परिचय कंचनताई गडकरी ने दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. ऋचा सुगंध ने किया।

स्वर्गीय भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर की विशेषताएं : 6000 वर्ग फुट का निर्माण, प्रतीक्षा क्षेत्र सहित पूर्णतः वातानुकूलित प्रणाली, पूरी तरह से कागज रहित संचालन, उच्च क्षमता वाले सर्वर, तकनीकी रूप से योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी, एमआरआई।

भारत में निर्मित मशीनें : 1.5 टेस्ला हाई-एंड इमेजिंग, 16 चैनल, म्यूजिक तकनीक छवि गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, तेजी से स्कैन करने में सक्षम बनाती है।

सीटी स्कैन : भारत में निर्मित मशीनें, बड़े शरीर वाले रोगियों के लिए बड़ा बोर, कम समय में स्कैन - केवल 6 सेकंड में पूरी छाती का स्कैन। बीआईएस, एईआरबी, सीडीएससीओ अनुमोदित : डिजिटल एक्स- रे, उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल एक्स-रे सेवा, डायलिसिस, 5 उच्च गुणवत्ता वाली डायलिसिस मशीनें।

कपड़ा क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए बने समिति

मुंबई – सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत नई सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समान मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। प्रत्येक विभाग को अपने अधीन कताई मिलों के लिए अतिरिक्त प्रावधान करना चाहिए। साथ ही, वस्त्र क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वस्त्र और ऊर्जा विभाग की एक समिति गठित की जानी चाहिए, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी कताई मिलों को 5,000 रुपये प्रति चाटी की दर से ऋण पर ब्याज अनुदान योजना का विस्तार करते हुए, उनका आधुनिकीकरण और श्रेणीकरण किया जाना चाहिए। राज्य में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत बंद मिलों को पुनः खोलने के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। उसके आधार पर, बंद मिलों को पुनः खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। एकीकृत एवं सतत वस्त्र नीति 2023-28 में आवश्यक संशोधन किए जाएं। साथ ही, सहकारी कताई मिलों और सहकारी पावरलूम संस्थाओं से सरकारी बकाया राशि की वसूली के संबंध में नीति तैयार की जाए। साथ ही, राज्य के सभी पावरलूमों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। पुणे में रेशम निदेशालय द्वारा उपयोग में लाए जा रहे भवन की मरम्मत और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। इस बैठक में नए महाराष्ट्र राज्य वस्त्र विकास महामंडल का निर्माण, वस्त्र आयुक्तालय और रेशम निदेशालय का विलय कर वस्त्र और रेशम आयुक्तालय का गठन, सहकारी कताई मिलों से अतिरिक्त भूमि की बिक्री की अनुमति देने की योजना, कताई मिलों को पुनर्वास ऋण प्रदान करने के लिए एक नई योजना तैयार करना और कताई मिलों को पट्टे पर देने की योजना, सहकारी कताई मिलों की परियोजना रिपोर्ट का मूल्य 80.90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 118 करोड़ रुपये करने की कार्रवाई।

प्रदेश में रिकॉर्ड 102 रोजगार मेले, एक ही दिन में 57 हजार रजिस्ट्रेशन, 27 हजार को नौकरी

मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन विभाग द्वारा आयोजित राज्यव्यापी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले में रिकॉर्ड 57 हजार युवाओं ने पंजीकरण कराया, जबकि एक ही दिन में 27 हजार युवाओं को रोजगार मिला। मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने स्पष्ट किया कि राज्य के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन को अविस्मरणीय बनाने और उनके करियर में एक नया अध्याय शुरू करने के उद्देश्य से कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवप्रवर्तन विभाग ने यह अभिनव पहल लागू की है।

वे मुंबई के गावदेवी स्थित शारदा मंदिर हाई स्कूल में आयोजित एक रोज़गार मेले में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह पहल जिला कौशल विकास, रोज़गार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर और शारदा मंदिर हाई स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की गई है और राज्य में ऐसे 100 मेले आयोजित किए जा चुके हैं। विकास की दूरदृष्टि रखने वाले और महाराष्ट्र को प्रगति के शिखर पर पहुँचाने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोज़गार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसी के अनुरूप यह पहल लागू की गई है। इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य के हज़ारों युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर यात्रा शुरू हो रही है। लोढ़ा ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ऐसी पहल जारी रहेंगी।

महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोज़गार मेले के माध्यम से हज़ारों युवाओं को निजी और सरकारी निगमों में काम करने के अवसर मिल रहे हैं। औद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिकी, बीमा, लॉजिस्टिक्स, प्रबंधन और सेवा क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं। मुंबई के गावदेवी स्थित शारदा मंदिर हाई स्कूल में आयोजित रोज़गार मेले में पाँच सरकारी निगमों सहित कुल 25 प्रतिष्ठानों ने भाग लिया। साथ ही, पाँच सौ युवक-युवतियों ने इस मेले के लिए पंजीकरण कराया।

कौशल विभाग के सहायक आयुक्त शैलेश भगत ने बताया कि इस सभा का मुख्य उद्देश्य रोज़गार उपलब्ध कराना है, लेकिन कौशल विभाग युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी और स्वरोज़गार पर परामर्श भी दे रहा है। इस अवसर पर कौशल विकास मार्गदर्शन अधिकारी विद्या शिंगे और मुकेश संखे भी उपस्थित थे।

यवतमाल में संजय राठौड़ ने कहा कि आज का युग कौशल पर आधारित है। इसलिए युवाओं को रोज़गार और स्वरोज़गार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करना चाहिए। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने का सपना देखता है। ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए युवाओं को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जिला कौशल विकास रोजगार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र की ओर से जाजू कॉलेज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं से संवाद करते हुए अपनी बात रख रहे थे।

सफलता का लुत्फ उठा रहीं रश्मिका

अपनी हालिया रिलीज 'छावा' की सफलता का लुत्फ उठा रहीं अभिनेत्री रश्मिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्रशंसकों को रात भर शूटिंग के बाद भोर में किए अपने नाश्ते की झलक दिखाई, जो उनके नाइट शूट या रात में किए अथक मेहनत को और भी खास बना देता है। 'छावा' की सफलता के बाद अभिनेत्री अब सलमान खान स्टारर 'सिकंदर' की शूटिंग में लगी हुई हैं। रश्मिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर दोने से भरी एक ट्रे की तस्वीर शेयर की, जिसमें दो मिनट के इंस्टेंट नूडल्स भरे हुए थे। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हमारे 4 बजे का स्नेक। यह हमारी नाइट शूट को और भी बेहतर बनाता है। रश्मिका ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि वह 'सिकंदर' की शूटिंग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वह एक एक्टर के अस्त-व्यस्त जीवन में वापस आ चुकी हैं। रश्मिका ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर उल्लेख किया कि वह 'सिकंदर' की नाइट शूट में व्यस्त हैं। उन्होंने कोरियाई अंदाज में दिल बनाती एक तस्वीर भी शेयर की। कैप्शन में लिखा, 'सिकंदर' नाइट शूट।

मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेता के तौर पर इस व्यस्त समय में वापस आ चुकी हूं। सिकंदर ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया था, जिसमें सलमान खान अलग अंदाज में नजर आए थे। इसमें अभिनेता लाल और हरे रंग की लाइटिंग के बीच बेलौस नजर आ रहे थे तो क्लोजअप में गुस्से से भरपूर! पोस्टर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था,सिकंदर ईद पर आ रहा है। इससे पहले जानकारी आई थी कि 'सिकंदर' के साथ अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म 'हाउसफुल 5' का ट्रेलर भी रिलीज होगा। निर्माता सलमान खान के 'सिकंदर' का टीजर बीते साल दिसंबर में जारी कर चुके हैं, जिसमें अभिनेता धमाकेदार एक्शन से भरे अंदाज में नजर आए। 'सिकंदर' में सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला 2014 की ब्लॉकबस्टर 'किक' के बाद एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं।

निकिता दत्ता ने बताया फिटनेस का राज

बॉलीवुड अभिनेत्री निकिता दत्ता ने अपनी फिटनेस का राज बताया है। निकिता दत्ता हमेशा फिटनेस की प्रबल समर्थक रही हैं। निकिता पिछले दस वर्षों से मैराथन में भाग ले रही हैं।फिटनेस के लिए उनका जुनून नजर आता है। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के साथ अपनी कसरत की दिनचर्या और स्वस्थ आदतों को साझा करती हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में, निकिता ने एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के बारे में बात

की। जब उनसे उनके आहार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुलासा किया।

जब से मैंने एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई है, तब से वह वास्तव में अपने जीवन के पिछले 13 वर्षों से इसका पालन कर रही हूं। उन्होंने कहा, मैंने पिछले 13 वर्षों में इंस्टेंट नूडल्स को नहीं छुआ है।कोई मैगी नहीं। मैंने किसी भी बिस्कुट को नहीं छुआ है। फिटनेस के प्रति निकिता की प्रतिबद्धता उनके अनुशासन और समर्पण का प्रमाण है। निकिता को आखिरी बार घरत गणपति में देखा गया था, जो मराठी सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और उनके प्रदर्शन को व्यापक सराहना मिली। वह अब जल्द ही सैफ अली खान और जयदीप अहलावत के साथ राम माधवानी निर्देशित फिल्म ज्वेल थीफ और द वॉकिंग ऑफ ए नेशन में दिखाई देंगी।

फिर से रिलीज होगी राजकुमार राव स्टारर शाहिद

वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता शाहिद आजमी के जीवन पर बनी राजकुमार राव स्टारर 'शाहिद' फिर से रिलीज होगी। फिल्म के निर्देशक हंसल मेहता ने रविवार को एक पोस्ट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की और प्रशंसकों को जानकारी दी। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म 'शाहिद' में राजकुमार राव मुख्य भूमिका में हैं, जिसके किरदार का नाम शाहिद आजमी है। फिल्म एक बार फिर से रिलीज के लिए तैयार है, जिसे लेकर फिल्म के कलाकारों के साथ ही निर्माता-निर्देशक हंसल मेहता भी काफी खुश और उत्साहित नजर आए। इंस्टाग्राम पर 'शाहिद' के एक पोस्टर के साथ हंसल मेहता ने लिखा,26 फरवरी को वर्सोवा होमेज स्क्रीनिंग पर स्क्रीनिंग की घोषणा से उत्साहित हूं। हंसल मेहता ने बताया कि फिल्म की दमदार कहानी वक्त के साथ और भी मजबूत हो गई है।

यामी गौतम ने अपनी यादें साझा कीं

आदित्य सुहास जंभाले के निर्देशन में बनी फिल्म 'आर्टिकल 370' को रिलीज हुए रविवार को एक साल हो गए। अभिनेत्री यामी गौतम ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी अपनी यादें साझा कीं और बताया कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक ऐसी कहानी है, जिसका सुनाया जाना जरूरी था। अभिनेत्री ने कहा कि शायद ही कोई फिल्म इतनी दमदार, अविश्वसनीय और शानदार वास्तविक कहानी लेकर आती है। राजनीतिक-एक्शन फिल्म का हिस्सा बनना खास लगता है। यामी ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की कुछ तस्वीरें शेयर कीं।

यह पत्र मालक, मुद्रक, प्रकाशक मिलिंद दहीवले ने एम.पी.ऑफसेट सिरसपेठ चौक, उमरेड़ रोड, नागपुर यहां से मुद्रित कर कार्यालय - फ्लैट नंबर 204, दूसरा माला, साकेत अपार्टमेंट, फूलमती ले-आउट, आरोग्यम क्लीनिक के पास, नागपुर-440027 से प्रकाशित किया. मिलिंद दहीवले, मो.9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईट: www.kendriyamanvadhikar.com

This paper is printed by owner, printer and publisher Milind Dahiwale at MP Offset, Siraspeth Chowk, Umred Road, Nagpur and published from office Flat No. 204, Second Floor, Saket Apartment, Phulmati Layout, Near Arogya Clinic, Nagpur 440027. Milind Dahiwale Mobile No. 9552011005. email : manvadhikar2012@gmail.com वेबसाईट: www.kendriyamanvadhikar.com

केन्द्रीय मानवाधिकार समाचार पत्र में प्रकाशित सभी लेख, छायाचित्र पर संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। न्यायिक कार्यवाही केवल नागपुर न्यायालय में होगी।

न्यूज गैलरी

कामचाटका में भूकंप, कई देशों में सुनामी का खतरा

रूस – कामचटका को दुनिया के सबसे तेज 10 शक्तिशाली भूकंप में शामिल किया गया है। इस भूकंप के बाद अभी कई देशों में बड़ी सुनामी का खतरा लगातार बना हुआ है। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में स्थित कामचाटका प्रायद्वीप के तट के पास स्थानीय समयानुसार लगभग 11:30 बजे रिक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आधुनिक इतिहास के 10 सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल किया गया है। इससे पहले दुनिया का सबसे तेज भूकंप 2004 में आया था। यह भूकंप करीब 20 किलोमीटर की गहराई में आया और इसके प्रभाव से पेत्रोपावलोस्क-कामचात्स्की शहर में भवनों को नुकसान और कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह शहर भूकंप के केंद्र से सिर्फ 119 किलोमीटर दूर स्थित है। इस भूकंप के बाद रूस, जापान और हवाई में सुनामी की चेतावनी और निकासी अभियान शुरू कर दिए गए। इसके अलावा फिलिपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और पेरू तक भी एडवायजरी जारी की गई है। पूरा प्रशांत क्षेत्र "रिंग ऑफ फायर" में आता है, जो एक भूकंपीय और ज्वालामुखीय रूप से अत्यंत सक्रिय इलाका है। अब तक दर्ज किए गए सभी 10 सबसे शक्तिशाली भूकंप रिंग ऑफ फायर में ही आए हैं। कुरील-कामचाटका ट्रेंच कामचाटका के पास स्थित है, जहां प्रशांत प्लेट लगातार ओखोत्स्क प्लेट के नीचे खिसक रही है। यह सबडक्शन जोन होने के कारण यहां भूकंप की तीव्रता और आवृत्ति दोनों अधिक होती है। यहां प्लेटें लगभग 75 मिमी/वर्ष की गति से टकरा रही हैं, जो कि भूगर्भीय मानकों के अनुसार तेज़ है। इसी गति के कारण इस क्षेत्र में विशाल भूकंप अक्सर आते रहते हैं। 1952 में भी इसी क्षेत्र में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था। दुनिया का सबसे तेज भूकंप 2004 में सुमात्रा में आया था। इसकी तीव्रता 9.3 थी। वहीं 2011 का तोहोकू-ओकी जापान (9.1 तीव्रता) का भूकंप, दोनों समुद्र तल को ऊपर-नीचे कर के विनाशकारी सुनामी का कारण बने थे। कामचाटका भूकंप भी इसी तरह का है। इसकी कम गहराई और बड़ी प्लेट सीमा के कारण इसका प्रभाव ज्यादा व्यापक रहा है। भूकंप के छह घंटे बाद तक यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार 35 से अधिक आफ्टरशॉक्स (5.0 तीव्रता से बड़े) आ चुके हैं। इस तरह के बड़े भूकंपों के बाद 7.5 तीव्रता तक के आफ्टरशॉक्स संभव होते हैं और ये कई हफ्तों या महीनों तक जारी रह सकते हैं। इस भूकंप ने एक सुनामी भी उत्पन्न की है, जो कुरील द्वीप, कामचाटका प्रायद्वीप और जापान के होक्काइडो क्षेत्र को प्रभावित कर चुकी है। आने वाले घंटों में यह हवाई, चिली और पेरू तक पहुंच सकती है।

इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा का अफ्रीका में खतरा

संयुक्त राष्ट्र – इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा का सबसे अधिक खतरा अफ्रीका में है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने एक नई रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट यूरोप और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने एक नई रिपोर्ट में कहा है कि इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के आतंकियों और उनके सहयोगियों का खतरा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सबसे अधिक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीरिया में भी जोखिम बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को वितरित की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम अफ्रीका का अल-कायदा से जुड़ा जमात नस्र अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमीन समूह और पूर्वी अफ्रीका का अल-कायदा से जुड़ा अल-शबाब अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र का लगातार विस्तार कर रहे हैं। जमात नस्र अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमीन समूह को जेएनआईएम के नाम से भी जाना जाता है। दोनों समूहों के खिलाफ प्रतिबंधों की निगरानी कर रहे विशेषज्ञों ने कहा कि आंशिक रूप से आतंकवाद-रोधी दबावों के कारण पश्चिम एशिया में इस्लामिक स्टेट को हुए नुकसान के कारण "संगठन का अफ्रीका के कुछ हिस्सों की ओर झुकाव जारी है।'' उन्होंने कहा, "क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के इरादे से मध्य एशिया और अफगानिस्तान में लौटने वाले विदेशी आतंकवादी लड़ाकों को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं।" विशेषज्ञों ने कहा कि इस्लामिक स्टेट यूरोप और अमेरिका के लिए "सबसे बड़ा खतरा" बना हुआ है। उनके अनुसार, अफगानिस्तान स्थित खुरासान समूह सोशल मीडिया और 'एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म' के जरिए लोगों को कट्टरपंथी बनाता है। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका में कई कथित आतंकवादी हमलों की साजिशें "काफी हद तक गाजा और इजरायल संघर्ष से प्रेरित" थीं, या आईएस द्वारा कट्टरपंथी बनाए गए लोगों द्वारा इन्हें अंजाम दिया गया था। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो मुस्लिम दुनिया से कई युवा 'जिहाद' के नाम पर अफगानिस्तान पहुंचे। इन्हीं में से एक था सऊदी अरब का अमीर और कट्टरपंथी विचारधारा वाला ओसामा बिन लादेन। लादेन ने अमेरिकी सहायता से अफगान मुजाहिदीनों के साथ सोवियत सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

नागपुर निवासियों के लिए मजबूत और आसान परिवहन प्रणाली उपलब्ध

बढ़ते विस्तार को आकार देने तीन चरणों में गतिशीलता योजना लागू करेंगे – मुख्यमंत्री

नागपुर – बढ़ते विस्तार में नागपुर के सभी हिस्सों में सुगम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के साथ-साथ अच्छी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। वर्तमान में नागपुर में सड़क सुविधाएं अच्छी होने के बावजूद कम होती जा रही हैं। वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ के साथ सभी हिस्सों को जोड़ने वाली नई सड़कों का निर्माण, अपर्याप्त चौराहों का विस्तार, महानगर में चलने वाली बसों के लिए स्टॉप, सार्वजनिक परिवहन बसों के लिए मार्ग, मेट्रो स्टेशनों से बसों की कनेक्टिविटी आदि जैसे बुनियादी विकास के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना तैयार की गई है। लगभग 25,567 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क के मसौदे को अधिक जनोन्मुखी और सशक्त बनाने

के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में जनता की राय जानने के निर्देश दिए हैं।

नागपुर महानगर की व्यापक गतिशीलता योजना के संबंध में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मेट्रो भवन में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, वित्त एवं योजना राज्यमंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल, सांसद श्यामकुमार बर्वे, विधायक श्रीकृष्ण खोपड़े, प्रवीण दटके, समीर मेघे, चरणसिंह ठाकुर, संजय मेश्राम, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, शहर पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंघल, महा मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रवण हार्डिकर, नागपुर सुधार ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय मीणा, जिला कलेक्टर डॉ. विपिन इटनकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि, महा मेट्रो के निदेशक अनिल कुमार कोकाटे, राजीव त्यागी सहित जिला प्रशासन और महा मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कोविड-पश्चात काल में महानगर के विस्तार ने गति पकड़ी है। वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का पंजीकरण हो रहा है। नागपुर ऐसी स्थिति में है जहाँ सड़कें अपर्याप्त हैं और वाहनों की संख्या अधिक है। हर दिशा में नए महानगर बन रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रमिक महानगर में आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है, इसलिए संबंधित अधिकारियों को नई योजना के अनुसार काम तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू रूप से जारी

मुंबई – यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मुंबई जाने वाले लेन में भूस्खलन के कारण 25 तारीख की शाम को कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया गया था। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने बताया है कि राजमार्ग के दोनों लेन पर यातायात सामान्य रूप से सुचारू रूप से चल रहा है। एक्सप्रेसवे पर शाम 6:10 बजे 45/300 किलोमीटर पर मुंबई जाने वाली लेन में पेड़ की टहनियाँ और कुछ मिट्टी का मलबा सड़क पर गिर गया। मीडिया में इसकी खबरें आईं, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। एमपीईडब्ल्यू पॉइंट पर तैनात टीम ने जेसीबी और मशीनरी की मदद से शाम 6:45 बजे इसे पूरी तरह से हटा दिया। हाईवे की दोनों लेन पर यातायात सुचारू रूप से शुरू हो गया है। तब तक एक लेन खाली हो चुकी थी। फिर 18:44 पर सभी लेन साफ़ कर दी गईं और 18:45 तक यातायात पूरी तरह से सुचारू हो गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने बताया है कि एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य है और सभी लेन में सभी वाहनों के लिए खुला है।

भंडारा पुलिस ने 14,83,000 रुपये मूल्य का स्कूल खाद्यान्न चावल किया जब्त

भंडारा – 26 जुलाई 2025 को जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आतंकवाद निरोधक दस्ते, भंडारा के सहायक पुलिस निरीक्षक गणेश बैरागी अपनी टीम के साथ जवाहरनगर पुलिस स्टेशन परिसर में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें एक गोपनीय सूचना मिली कि खरबी से गौरी रोड पर साईंबाबा राइस मिल के गोदाम के सामने एक संदिग्ध ट्रक खड़ा है। सूचना के आधार पर, टीम खरबी के साईंबाबा राइस मिल के गोदाम में गई और पाया कि आयशर कंपनी का ट्रक संख्या MH 40/A.K. 691, उस स्थान पर खड़ा था। चावल के बारे में पूछताछ की गई और दस्तावेज मांगे गए। उसने एक गोलमोल जवाब दिया और कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिखाया। टीम ने ट्रक चालक अनिल प्रभाकर रणदिवे को विश्वास में लिया और उससे बारीकी से पूछताछ की, और उसने बताया कि उक्त चावल स्कूल पोषण के लिए था, और चावल ठेकेदार अमित विनायक वाघ ने कहा कि इसे साईंबाबा राइस मिल खरबी / जवाहरनगर के गोदाम से लाया गया था। यह पुष्टि करने के बाद कि उक्त चावल स्कूल पोषण के लिए था, रविंद्र सोनटक्के, शिक्षण अधिकारी, प्राथमिक जि.प. भंडारा और उनके सहयोगी शिल्पा दिलीप निखाड़े (विस्तार अधिकारी), पंचायत समिति भंडारा को बुलाया गया और उन्होंने ट्रक में चावल का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि ट्रक में चावल स्कूल पोषण के लिए था। तत्पश्चात घटना स्थल को पंचायत के समक्ष ले जाकर विस्तार अधिकारी शिल्पा दिलीप निखाडे के समक्ष जप्ती पंचनामा कार्यवाही की गई, तथा ट्रक में 210 बोरी चावल, प्रति बोरी 50 किलोग्राम कुल 10,500 किलोग्राम चावल, कुल कीमत 4,83,000/- रूपये प्रति किलोग्राम चावल तथा आयशर कंपनी का ट्रक क्रमांक एम.एच.40/ए.के.2691 कीमत 10,00,000/- रूपये कुल 14,83,000/- रूपये अवैध रूप से अर्जित संपत्ति आरोपी 1) ट्रक चालक अनिल प्रभाकर रणदिवे उम्र 34 वर्ष, निवासी मुंढरी टोला, ताल. सड़क/अर्जुनी, जिला. गोंदिया, 2) ठेकेदार अमित विनायक वाघ उम्र 39 वर्ष, निवासी विनोबा भावे नगर नागपुर, 3) साईंबाबा राइस मिल मालिक सुनील भावराव गी-हेपुंजे उम्र 49 वर्ष, निवासी खरबी पुलिस स्टेशन जवाहरनगर अप.क्र. 276/2025 धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ धारा 33 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे, नितिनकुमार चिंचोलकर, स्थानीय अपराध शाखा भंडारा, भीमाजी पाटिल, पी.ओ. सेंट जवाहरनगर, एस.पी.ओ. गणेश बैरागी, एस.पी.ओ. राजकिरण मडावी, एस.एफ.आई. संजय कुरंजेकर, रविंद्र गभाने के मार्गदर्शन में की गई। प्रमोद वैद्य, विजय तायडे, योगेश सरवरे, शुभम कुलारकर, राजेश पंचबुधे, संदीप मते, वसंत गजभिये, बाला वरखड़े, लोकेश सिंगाड़े, नितिन भालाधरे ने सफलतापूर्वक कार्रवाई की।

प्रभावित 3 लाख 98 हजार किसानों को राहत के लिए 337.41 करोड़ स्वीकृत

मुंबई – राज्य सरकार ने फरवरी 2025 से मई 2025 तक राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण 3 लाख 98 हजार 603 प्रभावित किसानों के 1 लाख 87 हजार 53.21 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के नुकसान के लिए 337 करोड़ 41 लाख 53 हजार रुपये की निधि को मंजूरी दी है। इस संबंध में सरकारी निर्णय सहायता और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल द्वारा जारी किया गया है। फरवरी 2025 से मई 2025 तक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कृषि फसलों को हुए नुकसान के कारण छत्रपति संभाजीनगर विभाग में 67 हजार 462 किसानों के 34 हजार 542.46 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र की फसलों के लिए 59 करोड़ 98 लाख 20 हजार रुपये, पुणे विभाग में 1 लाख 7 हजार 463 किसानों के 45 हजार 128.88 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र की फसलों के लिए 81 करोड़ 27 लाख 27 हजार रुपये, नाशिक विभाग में 1 लाख 5 हजार 147 किसानों के 45 हजार 935.16 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र की फसलों के लिए 85 करोड़ 67 लाख 8 हजार रुपये, कोंकण विभाग में 13 हजार 608 किसानों के 4 हजार 473.69 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र की फसलों के लिए 9 करोड़ 38 लाख 24 हजार रुपये, अमरावती संभाग में 54 हजार 729 किसानों के 36 हजार 189.86 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए तथा नागपुर संभाग में 50 हजार 194 किसानों के 20 हजार 783.16 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए फसलों के लिए 34 करोड़ 91 लाख रुपए की सहायता दी गई है। इसमें 63 हजार रुपए की सहायता शामिल है। फरवरी से मई 2025 के बीच राज्य के कई जिलों में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने कहा कि सरकार बेमौसम बारिश के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और इन प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए तुरंत इस कोष को मंजूरी दे दी है।

तिलहन प्रसंस्करण इकाई के लिए आवेदन 31 तक करें

नागपुर – जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी रवींद्र मनोहरे ने अपील की है कि इच्छुक सरकारी, निजी उद्योग, किसान उत्पादक संगठन, कंपनियाँ और सहकारी समितियाँ राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन 2025-26 के अंतर्गत तिलहन प्रसंस्करण इकाइयों के

लिए आवेदन करें ताकि बीज संग्रहण और तेल निष्कर्षण की दक्षता बढ़ाई जा सके।

लाभार्थी चयन : तिलहन संग्रहण, तेल निष्कर्षण और तेल उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के लिए कटाई-पश्चात बुनियादी ढाँचे की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें मौजूदा बुनियादी ढाँचे की क्षमता या दक्षता में सुधार और बिनौला, नारियल, चावल की भूसी और वृक्ष-आधारित तिलहन (टीबीओएस) सहित खाद्य द्वितीयक स्रोतों से तेल उत्पादन शामिल है। इसमें सरकारी/निजी उद्योगों, किसान उत्पादक संगठनों/कंपनियों (एफपीओएस) और सहकारी समितियों को बीज संग्रहण और तेल निष्कर्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

अनुदान सीमा : तेल निष्कर्षण इकाई (10 टन क्षमता) तथा तिलहन प्रसंस्करण हेतु मशीनरी एवं उपकरण तथा परियोजना लागत की गणना करते समय ऐसे व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा। अनुदान राशि चयनित लाभार्थियों द्वारा संयंत्र क्रय करने, उसका स्थलीय परीक्षण करने तथा परियोजना चालू होने के पश्चात ही आधार से जुड़े राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए।

यह बैंक ऋण से संबंधित है तथा इच्छुक प्रसंस्करण भागीदार को केंद्र सरकार की ग्रामीण भंडारण योजना/नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना बैंक में प्रस्तुत करनी होगी। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित आवेदक उक्त मद के लाभ हेतु पात्र होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई के अंत तक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए मंडल कृषि अधिकारी / तालुका कृषि अधिकारी / प्रभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।

किसानों के वित्तीय हितों की रक्षा करने – फसल बीमा सुरक्षा कवर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम की अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिमों को कम करके देश के मेहनती किसानों के वित्तीय हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों ने हाल ही में खरीफ मौसम के लिए संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करना शुरू किया है। इस योजना के बारे में जानकारी इस प्रकार है...

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। देश में अब तक 23 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल चुका है। किसानों को 1.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना में 78 करोड़ से अधिक किसान शामिल हो चुके हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं : खरीफ मौसम बीमा योजना में भागीदारी के लिए पात्र फसलें: अधिसूचित क्षेत्रों के किसान चावल (धान), खरीफ ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, करेला, कपास और प्याज जैसी अधिसूचित फसलों में भाग ले सकते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु : योजना में भाग लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। इस योजना में भाग लेने के लिए किसान का एग्रीस्टैक पंजीकरण क्रमांक और ई-फसल सर्वेक्षण अनिवार्य है। अधिसूचित क्षेत्र में, अधिसूचित फसलों के सभी किसान इस योजना में भाग ले सकते हैं। ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए योजना में भागीदारी स्वैच्छिक है। यदि ई-फसल सर्वेक्षण और बीमित फसल के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो बीमा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बीमा आवेदन भरने के लिए प्रति किसान (सीएससी) 40 रुपये का शुल्क तय किया है। यह शुल्क संबंधित बीमा कंपनी के माध्यम से (सीएससी) विभाग को दिया जाता है। इसलिए, किसान अपने बीमा प्रीमियम के अलावा वाहन चालक को कोई अन्य शुल्क (सीएससी) न दें। यदि कोई आवेदक फर्जी या धोखाधड़ी के माध्यम से बीमा योजना का लाभ उठाने की कोशिश करता है, तो उसे अगले पांच वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। स्वीकृत मुआवजा केंद्र सरकार के पोर्टल से सीधे आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा। सभी फसलों के लिए जोखिम स्तर 70 प्रतिशत है।

सीमांत उत्पादन : अधिसूचित क्षेत्र में, अधिसूचित फसलों का सीमांत उत्पादन, उस फसल के जोखिम स्तर को ध्यान में रखते हुए, पिछले सात वर्षों के उच्चतम उत्पादन को पांच वर्षों के औसत उत्पादन से गुणा करके निर्धारित किया जाता है।

बीमा कवरेज आइटम इस प्रकार हैं : यदि फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज, बुवाई से कटाई तक की अवधि के दौरान विभिन्न प्राकृतिक कारकों, कीट और रोग प्रकोप आदि के कारण उस राजस्व सर्कल के लिए निर्धारित उपज से कम हो जाती है, तो उस राजस्व सर्कल में उस फसल के लिए बीमित सभी किसानों को समान मुआवजा मिलेगा।

योजना को क्रियान्वित करने वाली बीमा कंपनी और संबंधित जिलों का नाम इस प्रकार है :

1) भारतीय कृषि बीमा कंपनी, मुंबई - अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सोलापुर, जलगांव, सातारा, वाशिम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार, परभणी, वर्धा, नागपुर, नांदेड़, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हिंगोली, अकोला, धुले, पुणे, जालना, गोंदिया, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगढ़, यवतमाल, अमरावती जिलों को कवर करती है।

2) आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, पुणे - लातूर, धाराशिव, बीड जिलों को कवर करती है।

फसलवार बीमा प्रीमियम दरें और बीमा प्रीमियम सब्सिडी : इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम दर वास्तविक दर पर ली जाएगी, हालाँकि, खरीफ और रबी मौसम के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम दर इस प्रकार है। (यह जिलेवार भिन्न होती है।)

1. खाद्यान्न और बाजरा फसले - बीमा राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर, जो भी कम हो। बीमा राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर, जो भी कम हो।

2. नकदी फसलें (कपास और प्याज) - बीमा राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर, जो भी कम हो। बीमा राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर, जो भी कम हो।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, वर्ष 2025-26 से किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम की सीमा खरीफ सीजन के लिए 2 प्रतिशत, रबी सीजन के लिए 1.5 प्रतिशत और खरीफ व रबी दोनों सीजन में नकदी फसलों के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार के 6 नवंबर, 2024 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीमा प्रीमियम दर में से किसान का हिस्सा काटने के बाद, शेष राशि राज्य और केंद्र सरकारों के माध्यम से बीमा प्रीमियम सब्सिडी के केंद्रीय हिस्से को सीमा के अनुसार दी जाएगी। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार शुष्क भूमि वाले जिलों में फसलों के लिए 30 प्रतिशत और सिंचित जिलों में फसलों के लिए 25 प्रतिशत का भुगतान करेगी।

बीमा क्षतिपूर्ति का निर्धारण कैसे किया जाएगा : खरीफ 2025 सीजन के लिए उत्पादन आधारित मुआवजे का निर्धारण करते समय, यदि राजस्व संभाग/तालुका में फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त औसत उत्पादन सीमा उत्पादन से कम है, तो मुआवजा राशि की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाती है। औसत उत्पादन की गणना करते समय, कपास, सोयाबीन, चावल जैसी चुनिंदा फसलों के मामले में, रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से प्राप्त उत्पादन को 50 प्रतिशत और फसल कटाई के माध्यम से प्राप्त उत्पादन को 50 प्रतिशत भार देकर फसल का औसत उत्पादन निर्धारित किया जाएगा। शेष फसलों के मामले में, फसल कटाई के माध्यम से प्राप्त उत्पादन को माना जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित किया जाने वाला मुआवज़ा सरकार द्वारा निर्धारित बीमा इकाई में फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज के आधार पर होगा। यदि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में उस वर्ष बीमित फसल की प्रति हेक्टेयर औसत उपज सीमांत उपज से कम हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि उस क्षेत्र के सभी बीमित किसानों को नुकसान हुआ है।

किसी बीमा घटक में सीमांत उपज या गारंटीकृत उपज, जोखिम स्तर सहित सभी फसलों के लिए उस मौसम के अंतिम 7 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों की औसत उपज होगी। इस योजना के अंतर्गत, खरीफ मौसम 2025 से रबी मौसम 2025-26 तक सभी फसलों के लिए जोखिम स्तर 70 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

बीमा योजना में भाग लेने के लिए किसान को क्या करना चाहिए : अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण लेने वाले किसानों को भी इस बीमा योजना में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, इसके लिए किसान को बीमा योजना में भागीदारी की अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पहले संबंधित बैंक को बीमा प्रीमियम का भुगतान न करने की लिखित सूचना देनी होगी। गैर-ऋणी किसानों को अपना एग्रीस्टॉक पंजीकरण संख्या, 7/12 अर्क, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और फसल बुवाई की स्व-घोषणा किसी अधिकृत बैंक में जमा करके और प्रीमियम का भुगतान करके भाग लेना चाहिए। इसके अलावा, आप हमारी सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की मदद से बीमा योजना में भाग ले सकते हैं या आप www.pmfby.gov.in पोर्टल की मदद ले सकते हैं। भाग लेने वाले किसान को फिर ई-पीक निरीक्षण रिकॉर्ड पूरा करना चाहिए।

न्यूज गैलरी

मॉयल ने वित्त वर्ष 2026 में अब तक का जुलाई माह का सर्वाधिक उत्पादन हासिल किया

नई दिल्ली – मॉयल ने जुलाई 2025 में प्रतिकूल मौसम के बावजूद 1.45 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (सीपीएलवाई) की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि है। मॉयल ने भारी वर्षा के बावजूद अप्रैल-जुलाई 2025 के दौरान मजबूत परिचालन का प्रदर्शन किया, जिसमें उत्पादन 6.47 लाख टन (वर्ष-दर-वर्ष 7.8 प्रतिशत वृद्धि), 5.01 लाख टन की बिक्री (पिछले वर्ष की इसी अवधि से 10.7 प्रतिशत अधिक) और 43,215 मीटर की अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग (पिछले वर्ष की इसी अवधि से 11.4 प्रतिशत अधिक) रही। मॉयल के सीएमडी श्री अजीत कुमार सक्सेना ने इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मॉयल टीम को बधाई दी और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद उत्पादन और बिक्री बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक महत्वपूर्ण पहल की सराहना की, जो स्थिरता को बढ़ावा देती है और नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा: ''यह एक सराहनीय प्रयास है, जो स्थिरता को बढ़ावा देता है और हमारे नेट-जीरो विजन को सशक्त बनाता है।''

मुंबई शहर कलेक्ट्रेट में राजस्व दिवस, विभिन्न गतिविधियाँ

मुंबई – मुंबई शहर जिले में राजस्व दिवस 1 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा और राजस्व सप्ताह 2025 1 से 7 अगस्त 2025 तक मुंबई शहर कलेक्टरेट के माध्यम से मनाया जाएगा। 1 अगस्त 2025 को राजस्व दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले उत्कृष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही, राजस्व सप्ताह के दौरान अन्य दिनों में जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी। मुंबई शहर जिले के आम नागरिकों के लिए निर्वाचन क्षेत्र/वार्डवार विभिन्न प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से नए मतदाताओं के पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर लोगों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए कार्रवाई की जाएगी और उनके संबंधित संगठनों और संस्थानों के साथ परामर्श करके उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा, मुंबई शहर में संपत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन किए जा रहे हैं और संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर अधीक्षक, भूमि अभिलेख, मुंबई शहर के माध्यम से की जाएगी।

अंगदान पखवाड़ा; आज से विभिन्न जागरूकता गतिविधियां

मुंबई – राज्य में अंगदान की दर बढ़ाने और अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे रोगियों को नया जीवन देने के लिए विभिन्न पहलों के साथ आज से अंगदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने पहल करते हुए आवेदन पत्र भरकर अंगदान का संकल्प लिया और इस अभियान का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री आबिटकर ने राज्य के लोगों से इस अभियान में भाग लेने और अंगदान का संकल्प लेने की अपील की है। राज्य में 3 अगस्त से 15 अगस्त तक अंगदान, जीवन रक्षक संजीवनी अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री प्रकाश अबिटकर ने इस दौरान व्यापक जनजागृति और समुदायोन्मुखी गतिविधियों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान में स्कूल, कॉलेज, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन, स्वास्थ्य संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से शामिल होंगे। यह अभियान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अंगदान के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों जैसे रोटो, सोटो, संभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समितियों और जेडटीसीसी, मुंबई, पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर के सहयोग से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। अंगदान एक सामाजिक प्रतिबद्धता है। इस मुद्दे पर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रभावी जनजागृति आवश्यक है। अभियान के माध्यम से अंगदान के बारे में भय, गलत धारणाओं और अंधविश्वासों को दूर करना और जनता तक वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करना महत्वपूर्ण है। इस पखवाड़े के दौरान, राज्य के प्रत्येक जिले, तालुका और स्वास्थ्य संस्थान स्तर, स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 अगस्त को जिला स्तर पर अंगदान करने वाले माता-पिता के परिवारों को सम्मानित कर अभियान को प्रेरक रूप दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में लोगों तक अंगदान के महत्व को पहुँचाकर महाराष्ट्र को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग ने जनता की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया है।

अश्विनी वैष्णव ने भावनगर, गुजरात से भावनगर-अयोध्या एक्सप्रेस, रीवा-पुणे (हडपसर) एक्सप्रेस और जबलपुर-रायपुर एक्सप्रेस को झंडी दिखाई

भावनगर – केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भावनगर, गुजरात से तीन नई एक्सप्रेस रेल सेवाओं – भावनगर-अयोध्या एक्सप्रेस, रीवा-पुणे (हडपसर) एक्सप्रेस और जबलपुर-रायपुर एक्सप्रेस को झंडी दिखा कर रवाना किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। भावनगर-अयोध्या साप्ताहिक रेलगाड़ी के शुभारंभ समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय श्रम और रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुखभाई मांडविया और उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन बंभानिया ने भाग लिया।

इस अवसर पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन तीनों रेलगाड़ियों का बहुत महत्व है। भावनगर-अयोध्या एक्सप्रेस संस्कृति और भक्ति को जोड़ेगी और भावनगर में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। पुणे आज एक प्रमुख औद्योगिक शहर है और रीवा, जबलपुर, सतना तथा मैहर से जुड़ा हुआ है। यह रेलगाड़ी इस जनजातीय क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण होगी।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का रेलवे के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है और वह रेलवे के विकास, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने और नेटवर्क का विस्तार करने पर सदैव बल देते हैं। पिछले 11 वर्षों में, रेलवे ने बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया है। इस अवधि में 34,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बनाई गईं, यानी औसतन 12 किलोमीटर प्रति दिन इनका निर्माण हो रहा है। यह एक ऐसा कार्य है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। वर्तमान में 1,300 स्टेशन पुनर्विकास के अधीन हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन आधुनिकीकरण कार्यक्रम है। विदेशों की अपेक्षा, जहां उन्नयन के दौरान स्टेशन और रेलगाड़ी का प्रचालन बंद हो जाता है, भारत में यह काम बिना किसी व्यवधान के तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि एक नई पोरबंदर-राजकोट रेलगाड़ी का जल्द ही दैनिक संचालन शुरू हो जाएगा। रानावाव स्टेशन पर एक नई कोच रखरखाव सुविधा, नई सरदिया-वंसजलिया रेलवे लाइन, भद्रकाली गेट, पोरबंदर शहर में एक नया फ्लाईओवर, दो नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और भावनगर में एक नया पोर्ट टर्मिनल पाइपलाइन में हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुंबई से अहमदाबाद तक देश की पहली बुलेट ट्रेन का संचालन जल्द ही शुरू होगा। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और एक बार चालू होने के बाद, मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय सिर्फ 2 घंटे और 7 मिनट होगा। बढ़ती यात्री सुविधाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एक नई अमृत भारत रेलगाड़ी शुरू की गई है। अब तक ऐसी करीब आठ रेलगाड़ियां शुरू हो चुकी हैं। अमृत भारत रेलगाड़ियों में वंदे भारत के समान सुविधाएं हैं, लेकिन काफी कम किराए पर आती हैं, जिससे वे अधिक यात्रियों के लिए सस्ती हो जाती हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है और प्रगति कर रहा है। एक नया भारत उभर रहा है और जैसे-जैसे परिवर्तन जारी है, रेलवे भी क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आधुनिकीकरण के साथ, नागरिकों को अब समय पर और अच्छी तरह से सुसज्जित रेल सेवाएं मिल रही हैं। रेलवे क्षेत्र में बदलाव विकसित भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र संतों, ऋषियों और भक्ति की भूमि है। अयोध्या रेलगाड़ी के माध्यम से अब इस क्षेत्र के लोगों को रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने इस पहल के लिए रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन बंभानिया ने रेल मंत्री का स्वागत किया और भावनगर को इस नई रेलगाड़ी के रूप में उपहार देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह रेलगाड़ी भावनगर की ऊर्जा को अयोध्या भक्ति के साथ जोड़ने वाले सेतु की तरह है और इससे न केवल भावनगर के लोगों को बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी लाभ होगा।

शिवराज ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का आह्वान किया

नई दिल्ली – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री की अपील को दोहराते हुए देशवासियों से देश में ही बने उत्पादों की खरीद करने की अपील की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल 2 अगस्त, 2025 को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के वितरण के अवसर पर देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज दोबारा से प्रधानमंत्री और सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताते हुए अपील को दोहराया और वक्तव्य के जरिए कहा कि-

"प्रिय बहनों और भाइयों– भांजे और भांजियों, "अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट-पतंगे भी, पशु-पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए... तू जी के ए दिल अपने देश के लिए। देश के लिए जीना कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है। कल उन्होंने अपील की, हम अपने घर में लगने वाला हर सामान, कोई भी वस्तु जिसकी हमारे घर पर ज़रूरत है, वो अपने देश में बनी हुई ही खरीदें।

मेरे बहनों और भाइयों, वही उत्पाद खरीदें- जो अपने गांव में बनते हो, पास के शहर में बनते हो, अपने जिले में बनते हो, प्रदेश में बनते हो, अपने देश में बनते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आज हम चौथे स्थान पर हैं, जल्द ही हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। हमारा देश 144 करोड़ की आबादी वाला बड़ा बाज़ार है।

'श्यामची आई' ने सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली – केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की। इसमें सुजय दहाके द्वारा निर्देशित फिल्म 'श्यामची आई' को सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार घोषित किया गया है। वहीं, आशीष बेंडे द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म 'आत्मपम्फलेट' और फिल्म 'नाल 2' को स्वर्ण कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार फिल्म जिप्सी के लिए बाल कलाकार कबीर खंडारे को दिया गया, जबकि त्रिशा ठोसर, श्रीनिवास पोकाले और भार्गव जगताप को फिल्म नाल 2 के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता घोषित किया गया। इस अवसर पर 40 फीचर फिल्म पुरस्कार, 15 गैर-फीचर पुरस्कार और 1 फिल्म-सर्वश्रेष्ठ लेखन पुरस्कार की घोषणा की गई। फीचर फिल्म पुरस्कारों के चयन के लिए जूरी का नेतृत्व आशुतोष गोवारिकर ने किया,

गैर-फीचर जूरी का नेतृत्व पी. शेषाद्रि ने किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म-सर्वश्रेष्ठ लेखन जूरी का नेतृत्व गोपालकृष्ण पई ने किया। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा तीन श्रेणियों - फीचर, गैर-फीचर और सर्वश्रेष्ठ फिल्म-सर्वश्रेष्ठ लेखन - में की गई। ये पुरस्कार जल्द ही प्रदान किए जाएँगे।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री पुरस्कार

हिंदी फ़िल्म "12वीं फ़ेल" को सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म का पुरस्कार मिला। शाहरुख़ ख़ान और विक्रांत मैसी को क्रमशः "जवान" और "12वीं फ़ेल" के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।

आशीष भेंडे को 'सेल्फ-पैम्फलेट ' के लिए पुरस्कार मिला। निर्देशक के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का पुरस्कार मराठी फिल्म आत्मपम्फलेट के लिए निर्देशक आशीष भेंडे को देने की घोषणा की गई।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फ़िल्में

सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म - जैकफ्रूट - ए जैकफ्रूट मिस्त्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक - सुदीप्तो सेन, द केरल स्टोरी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री - उर्वशी, उलोजुक्कू, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता - विजयराघवन और मुथुपेट्टई सोमू भास्कर, राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म - सैम बहादुर के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई।

केंद्र ने छत्रपति संभाजीनगर से परभणी रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी

मुंबई – "छत्रपति संभाजीनगर से परभणी रेलवे लाइन के दोहरीकरण को केंद्र सरकार से अंतिम मंज़ूरी मिल गई है। यह न केवल परभणी ज़िले के लिए, बल्कि पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है और मराठवाड़ा के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मराठवाड़ा के लोगों का वर्षों से जो सपना था, वह अब केंद्र सरकार के माध्यम से पूरा हो रहा है," राज्य मंत्री और परभणी ज़िले की पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डिकर ने कहा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्रपति संभाजीनगर से परभणी तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण को अंतिम मंजूरी दे दी है और इसके लिए 2,179 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य मंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डिकर स्वयं इस रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार प्रयास कर रही थीं। यह प्रयास सफल रहा है और 177 किलोमीटर लंबे डबल ट्रैक के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार

ालकमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डिकर ने आगे कहा, "इस मार्ग के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से केंद्र सरकार से किया गया अनुगमन सफल रहा है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अब इस मंज़ूरी से यह दोहरा मार्ग साकार हो जाएगा और छत्रपति संभाजीनगर और परभणी के बीच ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी।"

पालकमंत्री श्रीमती साकोरे बोर्डिकर ने कहा, "इस दोहरीकरण से न केवल नियमित यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि मराठवाड़ा के किसानों, व्यापारियों, छात्रों, पेशेवरों और उद्योगों को भी लाभ होगा। इसके अलावा, ट्रेनों की संख्या में वृद्धि से पूरे मराठवाड़ा की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठवाड़ा के विकास को लगातार प्राथमिकता दे रहे हैं। वे मराठवाड़ा में बुनियादी ढाँचे के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है कि पालकमंत्री साकोरे-बोर्डिकर ने कहा कि इस स्वीकृति प्रक्रिया में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अनुसरण भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है।

पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे ने पशुओं के लिए सुपर स्पेशियलिटी एम्बुलेंस समर्पित की

मुंबई –'समस्त महाजन' संस्था के 'अर्हम अनुकंपा प्रकल्प' के अंतर्गत मुंबई और मुंबई उपनगरों में गायों और अन्य पशुओं की सेवा के लिए एक सुपर स्पेशियलिटी पशु एम्बुलेंस का उद्घाटन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे के हाथों किया गया। उद्घाटन समारोह में संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी गिरीश शाह, ट्रस्टी परेश शाह के साथ-साथ समस्त जैन समाज के अनेक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संस्था 'समस्त महाजन' के अर्हम अनुकंपा प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू की गई उन्नत तकनीक से सुसज्जित यह एम्बुलेंस मुंबई, ठाणे और पालघर क्षेत्रों में गायों और अन्य घायल पशुओं का इलाज करेगी। समाज की विभिन्न गौशालाओं से घायल, बीमार गायों और अन्य पशुओं को अस्पताल पहुँचाने के लिए हाइड्रोलिक एम्बुलेंस महत्वपूर्ण साबित होगी। पशुओं की पीड़ा कम करने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है। पशु प्रेमियों की सेवा को अपना मुख्य लक्ष्य मानते हुए, पशुपालन मंत्री श्रीमती मुंडे ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इस पहल का विस्तार किया जाएगा। 'समस्त महाजन' एक संस्था है जो पिछले कई वर्षों से पशु कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। संस्था नियमित रूप से निःशुल्क पशु उपचार, भोजन वितरण, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की सहायता जैसी विभिन्न गतिविधियाँ करती है। पिछले 36 महीनों में संस्था की ओर से अब तक गायों और अन्य घायल पशुओं सहित 92,500 पशुओं का उपचार किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने मोर्शी में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय की आधारशिला रखी, कृषि का दर्जा मिलेगा

पेज 1 से आगे...

हालाँकि किसानों के लिए कर्ज़ माफ़ी ज़रूरी है, लेकिन संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार कदम उठाए जाएँगे। इसके साथ ही, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना के माध्यम से किसानों को सभी ज़रूरी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। सरकार के इन विभिन्न प्रयासों के माध्यम से कृषि में बदलाव का प्रयास किया जाएगा।

किसानों को बारह घंटे बिजली मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना लागू की जा रही है। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट मोर्शी में ही लागू किया गया है। सरकार के वादे के अनुसार, किसानों को अगले पांच साल तक मुफ्त बिजली मिलेगी। पहली बार बिजली क्षेत्र में सुधारों के कारण बिजली की दरें कम हुई हैं। अगले पांच वर्षों में, 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वालों का बिजली बिल आज की तुलना में 26 प्रतिशत कम हो जाएगा। सभी को अपना घर मिले, इसके लिए केंद्र सरकार की मदद से 30 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। आने वाले समय में, सर्वेक्षण से बचे हुए नागरिकों को भी अपना घर दिया जाएगा और बेघर-मुक्त महाराष्ट्र का सपना साकार होगा।

इसके साथ ही, 50,000 रुपये की सहायता से पांच लाख घरों पर सौर प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे जरूरतमंद नागरिकों को बिजली के बिलों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, यदि अतिरिक्त बिजली उत्पन्न होती है, तो सरकार उसे खरीदेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को हर तरफ से मदद करने और उनके जीवन को आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा।

यह गर्व की बात है कि पालकमंत्री श्री बावनकुले ने मोर्शी में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने विकसित महाराष्ट्र के लिए नीति तय की है और दिव्यांगों, किसानों और खेतिहर मजदूरों सहित समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने की नीति बनाई है। दिव्यांगों को 2,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि कर्ज मुक्ति की आवश्यकता वाले लोगों की मदद के लिए एक समिति बनाई जाएगी और विभिन्न निर्णय लिए जाएंगे। हर खेत तक जाने के लिए पक्की सड़क बनाई जाएगी और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि किसान अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुँचा सकें। साथ ही, आने वाले दिनों में चिखलदरा क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही, मोर्शी क्षेत्र में संतरा प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्री श्री राणे ने कहा कि मत्स्य महाविद्यालय का निर्माण अगले दो वर्षों में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस महाविद्यालय के कारण मछुआरों के अच्छे दिन आएंगे और वे आर्थिक रूप से सक्षम और समृद्ध बनेंगे। मछली को कृषि का दर्जा देने से कई रियायतों का लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों में मीठे पानी के मछुआरों को भी महत्व दिया जाएगा। इसके साथ ही, मत्स्य व्यवसाय में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मार्वल कंपनी के साथ समझौता

किया गया है। इससे मछुआरों के जीवन में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि मोर्शी स्थित महाविद्यालय में अच्छी शिक्षा के साथ-साथ उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएँगे। सांसद अनिल बोंडे ने परिचय में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलों की जानकारी दी।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कॉलेज भवन का शिलान्यास और आधारशिला का अनावरण किया। इस अवसर पर भोई समाज द्वारा मुख्यमंत्री का पुष्पमाला से अभिनंदन किया गया। साथ ही, जिले में पाँच सड़क विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बंधुओं को दोपहिया वाहन वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन क्षिप्रा मानकर ने किया। कुलपति डॉ. पाटिल ने आभार व्यक्त किया